मुख्य समाचार :–

- राज्य में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश के कारण पन्द्रह लोगों की मृत्यु, 16 लापता।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राहत–बचाव कार्यों की समीक्षा की; प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।
- प्रदेशभर में आज से दो अक्टूबर तक सेवा पखवाडे के तहत चार हजार से अधिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाएंगे।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं से आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस अपनाकर उसका सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करने का आह्वान किया।

बारिश/सामान्य जन जीवन प्रभावित

राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार रात से बारिश का दौर जारी है। इससे कईं स्थानों पर सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बारिश के कारण राज्य में पन्द्रह लोगों की मृत्यु हुई है। देहरादून जिले में हुई अतिवृष्टि से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि लापता 16 अन्य लोगों की तलाश जारी है। शासन और प्रशासन की ओर से राहत व बचाव अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और लगभग 900 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है।

समीक्षा

लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और राहत–बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्रवाई करने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापता लोगों की खोज और फंसे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राहत शिविरों में भोजन, पानी, चिकित्सा और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग को आपूर्ति बहाल करने और पानी की गुणवत्ता जांचने तथा स्वास्थ्य विभाग को संभावित बीमारियों को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। श्री धामी ने एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की कार्यशैली की सराहना की और आपदा बचाव में साहसिक कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिनों में सभी जिलों में पूरी सतर्कता बरती जाए और मौसम पूर्वानुमान को और सुदृढ़ किया जाए।

जिलाधिकारी देहरादून निरीक्षण

उधर, अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लेने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल मालदेवता, सहस्रधारा, मजयाडा और कार्लीगाड पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को राहत–बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों पर किराए में शिफ्ट होना चाहें तो तीन माह तक प्रति परिवार चार हजार रुपये किराया दिया जाएगा। उन्होंने बिजली, पानी और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता पर बहाल करने के निर्देश दिए।

डायवर्ट प्लान

देहरादून में आपदा से कई रास्ते और पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात प्रभावित है। देहरादून पुलिस ने विभिन्न मार्गों से आवागमन के लिए डायवर्ट प्लान जारी किया है।

राज्यपाल संबोधन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं से आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस अपनाकर उसका सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करने का आह्वान किया है। कल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित "एआई : विश्वास एवं भविष्य" अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल विज्ञान और तकनीक का विषय नहीं, बल्कि यह नैतिकता, मानवाधिकार और सामाजिक सद्भाव से भी जुड़ी है। उन्होंने एआई को विकास, समृद्धि और खुशहाली का प्रमुख साधन बताते हुए कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

सेवा पखवाड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत कर रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। पखवाड़े के दौरान उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों, जिला और उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों में 4 हजार 604 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में जांच, परामर्श और दवाओं की सुविधा मिलेगी। शिविरों में गर्भवती महिलाओं, टीबी मरीजों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को विशेष परामर्श मिलेगा। लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

ऑनलाइन प्रणाली

उत्तराखंड श्रमायुक्त कार्यालय ने ऑनलाइन लेबर सेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिससे श्रम कल्याण प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है। पहले यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी, जिससे अनियमितताएं और समीक्षा की कमी बनी रहती थी। खास बात यह है कि ये प्रणाली उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बिना किसी सरकारी व्यय के विकसित की है, जिसमें एक निजी बैंक ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत सहयोग किया। इस पहल से एक वर्ष में 60 प्रतिशत राजस्व वृद्धि, 10 हजार प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और सेस प्रबंधन में पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार दर्ज हुआ है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परियोजना की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए मॉडल बताया है।

विश्वकर्मा जयंती

आज विश्वकर्मा जयंती है। भगवान विश्वकर्मा को सृजन, निर्माण और तकनीकी कौशल का देवता माना जाता है। इस दिन को खास तौर पर इंजीनियरों, कारीगरों, तकनीशियनों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि यह कर्मशीलता, रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का उत्सव भी है। विश्वकर्मा जयंती का यह पर्व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्यमियों, शिल्पियों व श्रमवीरों को सम्मानित करने का भी अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा जयन्ती हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि हर रचना, हर निर्माण एक तपस्या है।

प्रवेश तिथि बढोतरी

उत्तराखंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों–आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दी गई है। राजकीय आईटीआई बेतालघाट, नैनीताल में कार्यरत कुमाऊं मंडल के उप नोडल अधिकारी (प्रवेश) राजेंद्र पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चयनित प्रशिक्षार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें पहला वर्ष संस्थान में और दूसरा वर्ष चयनित कंपनी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में पूरा होगा। प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता के साथ बेहतर कौशल विकास का अवसर मिलेगा।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों ––

उत्तराखंड में अतिवृष्टि के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य शीर्षक में शामिल किया है। दैनिक जागरण लिखता है – भयानक गर्जना के साथ दून पर बरपा कहर। अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है – अब देहरादून में आपदा, 13 पुल क्षतिग्रस्त, 62 सड़कें बंद, कई भवन ध्वस्त।

हिन्दुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है – नदी–नालों पर कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटें। अमर उजाला लिखता है – आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राष्ट्रीय सहारा लिखता है– रावत व बचाव कार्यों में नहीं रहेगी कसर।

अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति से रोक हटा दी गई है। इस समाचार पर नवोदय टाइम्स ने लिखा है – हाईकोर्ट ने सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन समितियों की याचिका पर की सुनवाई।